

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 17 जुलाई 2025, समय 1305 (05 मिनट))

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जायेगा और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जायेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। करनाल को भी आज स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलेगा ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल-उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बा०त्तरी होगी।

यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में एक सौ जिलों की पहचान की जाएगी।

केन्द्र सरकार दस लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित 'जन सेवा केन्द्र दिवस' कार्यक्रम में इसकी घोषणा की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर की स्वच्छता को बनाए रखने और इसे निरंतर बेहतर बनाने के लिए निगम पार्षदों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए पार्षदों से आह्वान किया कि वे निगम अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करें।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने पार्षदों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी जनसमस्याओं के समाधान में कोताही बरतता है, तो वे सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 18 परिवाद रखे गए, मुख्यमंत्री ने 15 परिवादों का निपटारा करते हुए तीन मामलों को आगामी बैठक तक लंबित

रखने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों से आगामी बैठक में स्टेटस रिपोर्ट लेकर आने के निर्देश दिए।

बल्लभगढ़ विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में नहर पुल से तिगांव रोड तक बनने वाली दो मार्गीय सड़क के सौंदर्यकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया।

विधायक ने बताया कि यह सड़क आधुनिक तरीके से बनाई जाएगी। इसके तहत रोड के दोनों ओर टाइल्स बिछाई जाएंगी, साथ ही स्ट्रीट लाइट्स लगाकर इसे आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जाएगा।

इस परियोजना पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आएगी। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा एह कार्य किया जाएगा ।

श्री मूलचंद शर्मा ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं कब्जे हटा लें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते थे, जबकि भाजपा सरकार में उन कब्जों को हटाकर आमजन के हित में सामुदायिक भवन व अन्य सरकारी इमारतें बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही सेक्टर-3 पुलिस चौकी रोड, सौ फीट रोड और तिगांव रोड पर भी विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन महानगर विकास प्राधिकरण इन सभी सड़कों का सौंदर्यकरण कार्य शीघ्र प्रारंभ करेगा।

हरियाणा सरकार राजस्व सुधारों में तेजी से काम कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर मानचित्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण और पूरी तरह से कागज़ रहित संपत्ति पंजीकरण प्रणाली का कार्य शामिल है।

वित्त आयुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर जोर दिया और अधिकारियों को तत्तिमा अद्यतनीकरण कार्य- भूमि भूखंड मानचित्रों के डिजिटलीकरण और सत्यापन को अगस्त 2025 तक पूरा करने का भी निर्देश दिया।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 1,221 सीमा स्तंभ स्थापित करने पर जोर दिया गया है। स्तंभ लगाने का कार्य पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और करनाल सहित कई जिलों में होगा। एस ओ आई सर्वेक्षणों पर आधारित मानचित्र संबंधित जिलों के साथ साझा किए गए हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है।
